दूसरों को समझाने से बेहतर है खुद को समझा लेना।
– अज्ञात

समस्याओं की कतार

देश कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा है, तब समुद्री तूफान और टिड्डी दलों के हमलों ने कुछ इलाकों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों को अब पूरे तालमेल के साथ ऐतिहासिक चुनौतियों के इस दौर को सफलतापूर्वक पार करना होगा।

नेहा अग्रवाल।

अभी जब देश अपनी पूरी ताकत झोंक कर कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा है, तब समुद्री तूफान और टिड्डी दलों के हमलों ने कुछ इलाकों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। अम्फान जैसे तूफान सामान्य स्थितियों में भी ऐसा बड़ा झटका लेकर आते हैं कि उससे उबरने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनका मुकाबला करने की कल्पना भला किसने की होगी? वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की बदौलत ऐसे तूफानों में अब पहले जैसी चौंकाने वाली बात नहीं रह गई है।

कई दिन पहले से पता होता है कि तूफान कितनी गति से किस दिन कितने बजे किस इलाके में आएगा। यही वजह है कि बचाव तैयारियां पहले से कर ली जाती है और हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होने पाती। इसके बावजूद अम्फान तूफान ने ओड़िशा और पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने की बात कही है।

बहरहाल, अभी की स्थितियों में इस तूफान से दोनों राज्यों में हुए वास्तविक नुकसान की सटीक जानकारी हासिल करने में एकाध हफ्ता लगेगा। सरकारी तंत्र के संसाधन यूं ही काफी सीमित हैं, और उनका बड़ा हिस्सा अभी कोरोना महामारी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में लगा है। ऐसे में तूफान से दूरदराज के क्षेत्रों में कितने पेड़ गिरे, कितनी सड़कें और पुल टूटे, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए और कितने बड़े इलाके में समुद्री पानी पहुंच जाने से खेतों में सालोंसाल न जाने वाला नमक बिछ गया, यह सब जल्दी पता करने का कोई तरीका सरकारों के पास नहीं है।

उधर देश के पश्चिमी हिस्से पर नजर डालें तो पाकिस्तान की खेती तबाह कर रहे टिड्डी दलों के राजस्थान की सीमा को पार करते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में हरियाली चाट जाने की खबर भी कम गंभीर नहीं है। उज्जैन, मंदसौर, नीमच, आगर–मालवा और आसपास के अन्य जिलों के किसान अभी थाली और ड्रम पीटकर इन टिड्डी दलों को भगाने का जतन कर रहे हैं।

कुछ इलाकों में सरकारी कर्मचारियों ने कीटनाशकों का छिड़काव भी किया है। लेकिन ये उपाय ज्यादा असरदार नहीं साबित हो रहे। एक बार इन टिड्डी दलों को अपनी अगली पीढ़ी तैयार करने का मौका मिल गया तो इन्हें आसपास के राज्यों में फैलने से रोकना लगभग असंभव हो जाएगा और अगले दो–तीन साल तक ये भारतीय खेती का सिरदर्द बनी रहेंगी।

इस कोरोना काल में तूफान और टिड्डी दलों के नुकसान से निपटने का काम साथ–साथ करना सरकारी तंत्र के लिए कितना मुश्किल है, यह समझा जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि केंद्र और राज्य सरकारों को अब तक के सभी आग्रहों–पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर पूरे तालमेल के साथ ऐतिहासिक चुनौतियों के इस दौर को सफलतापूर्वक पार करना होगा।

हमारा जीवन

अशोक वोहरा।

हमारा जीवन बहुत तेजी से बस भागता जा रहा है... ये बात हम जानते हैं कि इतनी तेजी से भागता हुआ हमारा जीवन बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। अगर हम सौभाग्यशाली हुए तो हम किसी जिम की मेंबरशिप लेकर, योगा क्लास जॉइन कर या फिर ध्यान करने की कला सीखकर बेहतर स्वास्थ्य का आनंद भी उठा सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग टी.वी. के सामने सोफे पर लेटकर रिमोट उठाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यहां आपके पास विकल्प है। ऊर्जा से परिपूर्ण वास्तविक भोजन। परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक रूप से समय बिताना। किसी गार्डन या पार्क में ताजी हवा और खिली धूप में बैठकर स्वयं के साथ समय बिताना। हम सभी इंसान हैं, जब हम शांति से बैठकर खुली हवा का आनंद उठाते हैं तब हम अपने शरीर को स्वस्थ और संतुलित होने का चांस मुहैया करवाते हैं।

संपादकीय

लोग लड़ें कोरोना से

बताया जाता है कि गंगा नदी के पानी में विशेष प्रकार के जैविक तत्व होते हैं जो रोगकारक वायरसों को रोकने में प्रभावी हो सकते हैं। अतः पैकेट में गंगाजल की एक शीशी भी पहुंचाई जा सकती है। देश के नागरिक स्वयं कोरोना के संकट से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे और इसमें खर्च भी बहुत मामूली आएगा। सरकार को चाहिए कि इन उपायों का आर्थिक मूल्यांकन कराए और सस्ते तथा कारगर उपायों को लागू करे। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर अर्थव्यवस्था को बंद रखने से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे और अर्थव्यवस्था भी अनायास बंद रहेगी। एक और उपाय यह है कि हम अपनी जनता की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं। आयुर्वेद में और हमारी जीवन शैली में हल्दी, तुलसी, नीम, अदरख, मुलेठी आदि के प्रयोग को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बताया गया है। सरकार जनता को प्रेरित करे कि वह इनका सेवन बढ़ाए।

सरकार एक अभियान शुरू करे जिसके अंतर्गत इम्यूनिटी बढ़ाने वाली वस्तुओं का पैकेट बनाकर देश के हर नागरिक के घर पर पहुंचाया जाए। उत्तराखंड सरकार ने मेरे घर पर मुफ्त सैनिटाइजर और मास्क भेजा। इसी प्रकार हल्दी, नीम आदि के पैकेट बनाकर देश के हर परिवार को वितरित किए जाएं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और करोना का संकट कम हो जाएगा। ऐसा करके हम देश की अर्थव्यवस्था को तत्काल चालू कर सकते हैं। इन उपायों को लागू करने में सरकार पर तनिक भी बोझ नहीं पड़ेगा।

व्यक्ति के जीवन का आर्थिक मूल्य आंकने के लिए अर्थशास्त्र में लोगों से पूछा जाता है कि एक वर्ष अधिक जीने के लिए वे कितनी रकम देने को तैयार होंगे।

हर व्यक्ति पर नजर

भरत झुनझुनवाला।

ब्राजील ने कोविड का सामना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। निर्णय लिया कि जितना संक्रमण होता है उसे बर्दाश्त कर अपने नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। उस देश में जितने लोग मरे उनका आर्थिक मूल्य वहां की सरकार अदा किया। व्यक्ति के जीवन का आर्थिक मूल्य आंकने के लिए अर्थशास्त्र में लोगों से पूछा जाता है कि एक वर्ष अधिक जीने के लिए वे कितनी रकम देने को तैयार होंगे। मान लीजिए, सामान्य व्यक्ति एक वर्ष अतिरिक्त जीने के लिए दो लाख रुपये देने को तैयार है और उसकी वर्तमान आयु 50 वर्ष है, जबकि नागरिकों की औसत आयु 70 वर्ष है। औसत के अनुसार उसकी 20 वर्ष की आयु शेष है। तब उसकी आज मृत्यु का आर्थिक मूल्य 20 वर्ष गुणे 2 लाख रुपये यानी 40 लाख रुपये होगा।

अमेरिका में उपरोक्त आधार पर एक मृत्यु का आर्थिक मूल्य 1 करोड़ अमेरिकी डालर आंका गया है। ब्राजील का 50 लाख डॉलर मान लें, तो अपने यहां हुई 21,000 मौतों का आर्थिक मूल्य 110 अरब डॉलर ब्राजील अदा कर चुका है जो उसके जीडीपी का 6 प्रतिशत बैठता है। मौत का सिलसिला वहां थमा नहीं है, अतः कुल आर्थिक मूल्य बहुत भारी पड़ेगा। यह उपाय हर

जगह के लिए मान्य नहीं है। चीन ने विशेष ध्यान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर दिया है। हर व्यक्ति जो सड़क पर आता है उसके आवागमन पर कंप्यूटर से नजर रखी जाती है। किसी भी दुकान में प्रवेश करते समय उसे कंप्यूटर से स्वीकृति लेनी पड़ती है और बाहर निकलते समय बताना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल कंप्यूटर से ज्ञात हो जाता है कि वह किन लोगों के संपर्क में आया होगा।

इससे यह पता करना खास मुश्किल नहीं होता कि किन लोगों में संक्रमण फैलने का अंदेशा है और किन्हें क्वारंटीन में रखने की जरूरत है। इस व्यवस्था के साथ गड़बड़ी यह है कि इसमें सूचना के दुरुपयोग की भारी संभावना है क्योंकि हर व्यक्ति किस समय कहां पर गया और किससे मिला, इसकी सूचना सरकार के पास पहुंच जाती है। सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर भी शिकंजा कस सकती है। फिर यह व्यवस्था भी मुफ्त तो नहीं है। इसे लागू करने का भी खर्च आएगा। हर दुकान में सेंसर लगाने होंगे। अपने देश के लिहाज से देखें तो यहां इंटरनेट का प्रसार भी इतना ज्यादा नहीं है कि संपूर्ण जनता को एक ऐप के माध्यम से ट्रेस किया जा सके। इसलिए चीन की यह व्यवस्था हमारे लिए व्यावहारिक नहीं दिखती है।

न्यूजीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग को बखूबी अपनाया गया है। इसका भी आर्थिक मूल्य है। उदाहरण के लिए फैक्ट्रियों में उत्पादन आदि पर और कंस्ट्रक्शन कार्यों पर सरकार ने रोक लगाई थी जिससे आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मूल्य को कम किया जा सकता है। उपाय यह है कि हम सभी उत्पादक संस्थानों को पूरी तरह से कार्य करने की छूट दें, बशर्ते वे एक सरकारी 'कोरोना निरीक्षक' की नियुक्ति के लिए सरकार को आवेदन दें और उसकी सेवाएं हासिल करने के लिए सरकार को धन उपलब्ध कराएं। जैसे आपकी फैक्ट्री में 100 कर्मी काम करते हैं। आप एक कोरोना निरीक्षक की नियुक्ति करा सकते हैं। निरीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह आपके संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करे। आपको निरीक्षक का वेतन सरकार को देना होगा। ऐसा करने से सरकार पर स्वास्थ्य निरीक्षकों का भार नहीं पड़ेगा और हमारी आर्थिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी।

अष्टयोग-5065

	4	5		7		
	28	1	36	2	30	4
2	3			6		
	33	2	34	3	29	6
4	5		7		2	
	33	7	37		33	
1			4	5	6	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5064 का हल

7	4	5	2	3	6	1
5	38	3	32	1	27	7
4	3	7	5	6	1	2
3	30	2	40	7	32	6
6	1	4	7	2	5	3
2	24	1	36	4	30	5
1	3	6	7	5	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन

मोहन। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी हो सकेगा। अपने देश में लगभग एक करोड़ सरकारी अध्यापक हैं। जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है उन्हें पूर्णतया बंद किया जा सकता है। इससे उपलब्ध हुए शिक्षकों को वर्तमान संकट की अवधि के लिए कोरोना निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। औद्योगिक, शैक्षिक और अन्य संस्थानों को इन कोरोना निरीक्षकों की देखरेख में खोला जा सकता है। भारतीय रेल के लगभग 16 लाख कर्मचारी हैं। ट्रेनों और स्टेशनों की संख्या को आधा किया जा सकता है। उपलब्ध हुए कर्मियों को कोरोना निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक डिब्बे में एक कोरोना निरीक्षक को नियुक्त किया जा सकता है जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन कराए और तदनुसार रेल टिकट का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। बसों की भी संख्या कम करते हुए कोरोना निरीक्षक को नियुक्त किया जा सकता है।